RAIL COACH FACTORY MEN'S UNION
KAPURTHALA (Regd. No. 56)

Affiliated to : Hind Mazdoor Sabha & All India Railwaymen's Federation
Recognized by : Administration of Rail Coach Factory, Kapurthala (Ministry of Railways)
Zonal Office : Near Reception ADMIN BLOCK Tele : RLY-94075
Website : www.rcfmu.blogspot.in

Rajbir Sharma
President & Member WC/AIRF
486-D, RCF, Kapurthala-144602
Mob : 084370-48894
RLY-93395

Rajinder Singh
Zonal Secretary/AIRF
348-C, RCF, Kapurthala-144602
Mob : 098039-80322
RLY-94275

Jaswant Singh Saini
General Secretary
470-C, RCF, Kapurthala-144602
Mob : 084370-41681
RLY-94081

Date : 24. 6. 2015

प्रेस नोट

रेलवे के निजीकरण की तैयारी पर विरोध सप्ताह व काला दिवस

बी.जे.पी. की सरकार के प्रधानमन्त्री कार्यालय ने डा. विवेक देबराय की अध्यक्षता में गठित कमेटी "भारतीय रेल की पुर्नसंरचना" ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट पेश कर दी है । सही मायने में केन्द्र सरकार रेलवे का निजीकरण/प्राईवेटाईजेशन और विभाजन के अपने एजेन्डे की दिशा में आगे बढ़ रही है जिसे रोकना बहुत जरुरी है । केन्द्रीय कर्मचारियों के मजदूर संगठनों/फैडरेशनों ने 23 नवम्बर, 2015 को सुबह 6.00 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल का विगुल बजा दिया है पर मोदी सरकार के मजदूर विरोधी फैसलों को रोकने के लिये जहां हर कर्मचारी व उनके परिवारों को हड़ताल सफल करने की तैयारी करनी है वहीं आम जनता जिनको रेलवे के निजीकरण/प्राईवेटाईजेशन से क्या-क्या नुकसान होगा उस बारे में रेल कर्मचारियों/परिवारों व आम जनता को सचेत करने व हड़ताल को सफल बनाने के लिये आल इडिया रेलवेमेन्स फैडरेशन के आदेशानुसार ***दिनांक 23 से 29 जून, 2015 तक विरोध सप्ताह व 30.06.2015 को "काला दिवस"*** रेल कोच फैक्टरी मेन्स यूनियन द्वारा मनाया जा रहा है । देबराय की अन्तरिम रिपोर्ट की प्रमुख बातें निम्न प्रकार हैं :-

1. भारतीय रेल को कमर्शियल व सामाजिक दोनों रवेया अपनाना चाहिये ।
2. यात्री किराये में बढ़ोत्तरी के साथ यात्री-सेवा व सुविधाओं का भी विस्तार करना चाहिये ।
3. रेलवे इन्फास्ट्रक्चर कमेटी बनायी जाये ताकि आगे चलकर एफ.डी.आई. लागू करना सम्भव हो ।
4. रेलवे मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी बनाकर सभी प्रोडक्शन यूनिटों को इसके तहत लाया जाये ।
5. सरकार को प्राईवेट कम्पनियों की रेलगाड़ी व मालगाड़ी चलाने और कोच/इंजन के बनाने की इजाजत देनी चाहिये।
6. रेलवे रेगुलेटरी अथारिटी आफ इण्डिया का गठन होना चाहिये जिसके जिम्मे किराया और सर्विसेस-चार्जेज तय करने के साथ तकनीकी स्तर बनाये रखने का काम हो । इसका अलग बजट हो व रेल मंत्रालय से कोई लेना-देना न हो । रेल मंत्रालय पालिसी बनाये इसको लागू कराने की जिम्मेदारी इस अथारिटी की हो ।
7. रेलवे के ग्रुप "ए" की आठ सेवाओं को दो भिन्न सेवाओं में बांट दिया जाना चाहिये । पांच तकनीकी सेवाओं को मिलाकर भारतीय रेल तकनीकी सेवा व तीन गैर तकनीकी सेवाओं को मिलाकर भारतीय लाजिस्टिक्स सेवा ।
8. जो गतिविधियां रेल यातायात के मुख्य काम से सम्बन्धित नहीं है जैसे अस्पताल, रेलवे स्कूल, खान-पान, रियल एस्टेट, लोको/कोच/डिब्बा(सवारी/मालगाड़ी)/सामाननिर्माण,आर.पी.एफ. आदि को रेलवे में नहीं रखा जाना चाहिये।
9. कोलकत्ता मेट्रो को भारतीय रेल से अलग किया जाये । रेलों में काफी जोन है, इनका पुर्नगठन किया जाये । उप- नगरीय रेल पटरियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर बिछाई जायें ।
10. रेलवे के अलग बजट की व्यवस्था को धीरे-धीरे खत्म करना चाहिये और इसे आम बजट के साथ मिला देना चाहिये। केन्द्र सरकार और रेलवे के सम्बन्ध बिलकुल अलग-अलग होने चाहिये । व्यापक बजट समर्थन बन्द हो, लाभांश देने की व्यवस्था खत्म हो । जिससे रेल मंत्रालय खत्म हो जायेगा और इसे ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के साथ मिला देना चाहिये ।
11. निवेश के लिये संसाधन जुटाने के लिये एक निवेश सलाहकार कमेटी बनाई जाये जिसमें विशेषज्ञ, निवेश बैकर और सेबी (शेयर बाजार) व रिजर्व बैंक आदि के प्रतिनिधि हों ।
12. जोनल निर्माण विभागों को एक छतरी के नीचे लाया जाये जैसे आर.वी.एन.एल. व इरकान आदि ।

13. सरकारी क्षेत्र में देश भर में, अनुकम्पा भर्ती (सी.जी.) में जो पद्धति है वे ही रेलवे में अपनाई जाये । ऐसी भर्ती में परिवार के सबसे सर्वोत्तम को मैम्बर चुना जाये व दो साल में वह अपनी योग्यता, उस कैटेगरी की भर्ती परीक्षा के अनुसार प्रमाणित करे । लार्जेस व बंगला खलासी की भर्ती की समीक्षा की जाये ।
14. रेलवे के बाहर के अधिकारियों (आई.ए.एस.) के आदान-प्रदान को प्रोत्साहन दिया जाये ।
15. "ए" व "ए-1" क्लास रेलवे स्टेशनों पर गेजटेड अधिकारी लगाये जायें जोकि ग्रुप "ए" (क्लास वन) सेवा के हों ।
16. डी.आर.एम. स्तर पर अधिक टेन्डर-पावर दी जाये ।स्वंय वित्त पोषित आधार पर पद सजृन करने की पावर का विकेन्द्रीकरण हो । वित्त विभाग डी.आर.एम. के अधीन हो ।

आज भारत में भारतीय रेलवे सरकारी होने से आम लोगों को क्या फायदे हैं उसकी छोटी सी झलक :

- बार्डर पर लड़ाई लगने पर रेल ड्राईवर व गार्ड तुरन्त अपनी जान की परवाह किये बिना सेना को बार्डर पर लड़ने के लिये ले जाते हैं और यदि रेल प्राईवेट हो गई तो प्राईवेट मालिक सेना को बिना किराये के ट्रेन क्यों देगा या वर्तमान समय में सेना की रेजीमेन्ट एक शहर से दूसरे शहर को बदलती रहती है तो सरकारी रेलवे उन्हे रेल माल/सवारी डिब्बे तो देती ही है और समयानुसार बदली के लिये रेल-लाईन/सिग्नलिंग/पानी इत्यादि का प्रबन्ध भी करके देती है यदि रेलवे प्राईवेट हो गई तो प्राईवेट मालिक बिना पैसे लिये ये सुविधायें नहीं देगा ? इसमें थोड़ी सी देरी भी दुश्मन को फायदा पहुंचा सकती है और आम जनता का जान-माल का नुकसान हो सकता है ।
- सभी प्रकार की गम्भीर बीमारियों के रोगियों/विकलांग/अन्धे व्यक्तियों व इनके सहायता के लिये एक व्यक्ति को ट्रेन यात्रा में 50 प्रतिशत फर्स्ट/सेकेन्ड ए.सी., 75 प्रतिशत स्लीपर में व 25 प्रतिशत थ्री-टायर एसी/राजधानी/शताब्दी में किराये पर छूट मिल रही है कैंसर रोगियों को मान्यता प्राप्त असपताल में इलाज के लिये 100 प्रतिशत थ्री टायर एसी/स्लीपर में ,75 प्रतिशत फर्स्ट/सेकेन्ड एसी में किराये पर छूट मिल रही है ।
- 60 वर्ष के पुरुष को 40 प्रतिशत व 58 वर्ष की महिला को 50 प्रतिशत को किराये में छूट मिल रही है ।
- सभी प्रकार के सम्मानित पदक पाने वालों को 50 से 75 प्रतिशत तक किराये में छूट मिल रही है ।
- बेरोजगार वर्करों/शहीदों की विधवाओं/पढ़ने वाली लड़कियों को 75 प्रतिशत किराये में छूट मिल रही है । पढ़ने वाले लड़कों/बेरोजगार युवाओं को 50 प्रतिशत किराये में छूट मिल रही है ।
- रिसर्चर/स्पोटर्स पर्सन/ सेन्ट जान ऐम्बुलैन्स/स्काउट एण्ड गाईड/सालाना रैली के डेलीगेटों को 25 से 75 प्रतिशत किराये में छूट मिल रही है । किसानों की स्पेशल ट्रेन के लिये किराये में 33 प्रतिशत की छूट मिल रही है ।
- डाक्टरों को किराये में 10 प्रतिशत छूट मिल रही है ।
- दैनिक यात्री को सस्ते किराये पर एम.एस.टी. पास की छूट मिल रही है ।
- रेल टिकट पर 100 किलो वजन का सामान ले जाने पर प्रति टिकट छूट मिल रही है।
- स्टेशन पर बहुत से गरीब जिनके पास रोटी, कपड़ा, मकान नहीं हैं स्टेशन पर ही जन्म लेते हैं और वहीं मर जाते हैं ।
- स्टेशनों व गाड़ियों में बहुत से बेरोजगार लोग चाय, नमकीन, मूंगफली, पानी व कपड़े-स्वेटर बेच कर रोजगार कर रहे हैं।

रेल जब प्राईवेट होगी तो स्टेशन का मालिक और ट्रेन का मालिक ऊपर लिखे आम लोगों को क्या ये सुविधायें देगा ? कभी नहीं देगा तो रेलवे के प्राईवेटाइजेशन के खिलाफ रेलवे कर्मचारियों के साथ आम लोगों को भी 23 नवम्बर, 2015 को सुबह 6.00 बजे से हो रही अनिश्चितकालीन हड़ताल में कन्धे से कन्धा मिलाकर मजदूर-किसान-कर्मचारी विरोधी मोदी सरकार के खिलाफ लड़ना होगा और इस हड़ताल को सफल बनाकर हमेशा के लिये मजदूर विरोधी मोदी सरकार को रोकना होगा ।

(जसवन्त सिंह सैनी)
महा सचिव